



हिंदी भाषियों से द्वेष किए बिना, मराठी का प्रचार हर घर तक पहुंचाए : राज ठाकरे

रिपोर्ट : जमीर काज़ी, मुंबई
मराठी भाषा का मुद्दा महाराष्ट्र के हर घर तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन इसके लिए हिंदी भाषियों से नफरत करके नहीं, बल्कि इसे सकारात्मक रूप से पहुंचाया जाना चाहिए - ऐसा निर्देश मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सोमवार को अपने पदाधिकारियों को दिया।
वो वांद्रे के रंगशारदा सभागृह में आयोजित मार्गदर्शन सम्मेलन में आगामी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों के संदर्भ में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुंबई महानगरपालिका चुनाव में मनसे १०० प्रतिशत सत्ता में आने

वाली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर मैं समय आने पर बात करूंगा, आप अभी से जोर-शोर से तैयारी में लग जाएं।
राज ठाकरे ने आगे कहा, जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्हें मराठी बोलनी ही चाहिए - इसके लिए हमें आग्रहपूर्वक खड़ा रहना होगा। हमारी आंदोलनात्मक भूमिका से राज्य सरकार घबरा गई है, इसलिए वह यह भ्रम फैला रही है कि मनसे हिंदी भाषा के खिलाफ है। लेकिन सच यह है कि हमें किसी भी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन इस भूमि पर मराठी के अलावा कोई भाषा

थोपी नहीं जा सकती। मराठी के लिए मनसे ने जो भूमिका ली है, वह हर मराठी भाई तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। मगर इस काम में किसी से नफरत की जरूरत नहीं है। हिंदी भाषियों से नफरत किए बिना, अपनी मराठी अस्मिता को सकारात्मक ढंग से लोगों के सामने रखें।
राज ठाकरे ने आगे कहा कि पदाधिकारियों को अभी से अपने-अपने वॉर्ड में मनपा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। इस बार मनसे पूरी ताकत से महापालिका चुनाव में सत्ता में आएगी। स्थानीय समस्याओं पर

ध्यान केंद्रित करें, जमीन पर उतरकर काम करें। किसी के दबाव में आए बिना, पूरी आत्मविश्वास से काम करें। उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के फैसले को मुझ पर छोड़ दें, मैं सही समय पर उस पर बोलूंगा। हम दोनों भाई २० साल बाद फिर से एक साथ आए हैं - पार्टी में आपसी खींचतान और गुटबाजी को अब जगह न दें। नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, उन्हें स्वीकार करें और एकजुट होकर काम करें। आपसी मनमुटाव को खत्म कर, चुनावी काम में लग जाएं - ऐसा स्पष्ट संदेश भी राज ठाकरे ने इस अवसर पर दिया।

मौलाना आज़ाद महामंडल द्वारा कर्जधारकों के साथ धोखाधड़ी

व्यवसायियों को अपनी संपत्ति से बंधक हटवाना चाहिए-जे.डी.शाह

बीड (प्रेस रिलीज़)
राज्य में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के युवाओं को विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू करने के लिए सहारा देने वाली संस्था मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल द्वारा दी जा रही कर्ज योजना के तहत कई आवेदकों को मंजूरी पत्र तो दे दिए गए, लेकिन वास्तविक कर्ज नहीं दिया गया। इन मंजूरी पत्रों के आधार पर गारंटर की संपत्तियों पर बंधक (हिपोटेक) चढ़ा दिया गया।
लेकिन केंद्र सरकार के अधीन भारतीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (दिल्ली) की गारंटी न मिलने के कारण मौलाना आज़ाद महामंडल कर्ज वितरण करने में असमर्थ रहा। इस वजह से जो युवा व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, उनके साथ एक तरह से धोखाधड़ी हुई है।
बीड जिले में जिन नागरिकों की संपत्ति पर कर्ज मंजूरी के नाम पर बंधक चढ़ाया गया है, वे तुरंत जिला कार्यालय में संपर्क करें और बंधक हटवाएं। साथ ही, जिन दलालों ने कर्ज मंजूर कराने के नाम पर पैसे लिए हैं, उनसे अपनी राशि वापस लें और ग्राहक संरक्षण कानून के तहत मौलाना आज़ाद महामंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज करें - ऐसा आवाहन समाजसेवक जे. डी. शाह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किया है।
विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि मौलाना आज़ाद महामंडल के प्रबंध संचालक श्री ग. पिक मगदूम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक मौआम/वो.उ/२०२५/४७३८ दिनांक १७/०७/२०२४ के तहत बीड जिला प्रबंधक को सूचित किया है कि जिन आवेदकों को कर्ज मंजूर किया गया लेकिन वितरित नहीं किया गया, उन मामलों में गारंटर की संपत्ति पर चढ़े बंधक/गहाण को हटाने हेतु ना-हरकत प्रमाणपत्र (छजउ)

जारी करने की अनुमति दी जाए।
स्थिति का विवरण इस प्रकार है:
मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल (भारतीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम, नई दिल्ली के माध्यम से) अल्पसंख्यक समाज के ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता व कर्ज सुविधा प्रदान करता है।
मौजूदा समय में आंकड़े इस प्रकार हैं:
कुल प्राप्त कर्ज आवेदन: ११,९००
मंजूर किए गए प्रस्ताव: ७,०७६
वितरित कर्ज: ३,२५४
शेष लंबित प्रस्ताव: ३,८२२
उम्मीद से अधिक प्रस्ताव होने और केंद्र से नियमित रूप से निधि (फंड) प्राप्त न होने के कारण मंजूर हुए पात्र लाभार्थियों को भी कर्ज नहीं मिल पा रहा है, जिससे कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।
इन हालात में, जिन आवेदकों की संपत्ति तारण (बंधक) रखी गई है, लेकिन उन्हें कर्ज नहीं मिला, वे जिला कार्यालय में आवेदन करके बंधक हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कर्ज की राशि न मिलने की वजह से यह वित्तीय लेनदेन अधूरा है, इसलिए कानूनी रूप से संपत्ति पर बंधक कायम नहीं रह सकता।
इसलिए, जिन्होंने कर्ज मंजूरी की उम्मीद में संपत्ति बंधक रखी थी, वे अपनी संपत्ति से बंधक हटवाएं और यदि दलालों को कोई राशि दी गई है, तो वह भी वापस लें। ऐसा स्पष्ट आवाहन समाजसेवक जे. डी. शाह ने किया है।

मनोज जरांगे पाटील से डॉ. योगेश क्षीरसागर ने की शिष्टाचार भेंट

बीड (प्रतिनिधि), ४ अगस्त - मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीड विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगेश क्षीरसागर और डॉ. सारिका क्षीरसागर ने सोमवार (४ अगस्त) को जालना जिले के अंतरवली सराटी के पास स्थित अंकुश नगर में शिष्टाचार भेंट की।

पाटील और डॉ. योगेश



दो दिन पहले बीड में एक कार्यक्रम के दौरान मनोज जरांगे

क्षीरसागर की मुलाकात हुई थी। इसके बाद डॉ. क्षीरसागर ने

अपने सहयोगियों के साथ समय निकालकर यह सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा हुई।
संवाद के दौरान मिला सकारात्मक प्रतिसाद आगे की यात्रा के लिए नई ऊर्जा देने वाला है, ऐसा डॉ. योगेश क्षीरसागर ने कहा। इस अवसर पर संपादक गंगाधर काळकुटे, सरपंच अमोल बागलाने और देविदास जाधव उपस्थित थे।

खामोशी से बनाते
रहो पहचान अपनी !
हवाएँ खुद तुम्हारा
नाम गुनगुनाएंगी ॥

राष्ट्रवादी
कांग्रेस पार्टी
प्रदेश प्रवक्तापदी
भागवत तावरे
यांची नियुक्ती
झाल्याबद्दल
**हार्दिक
अभिनांदन..**

भागवत तावरे मित्र परिवार.बीड

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

जिला परिषद की स्कूलों की खस्ता हालत-शिक्षक और छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ाते और पढ़ते हैं

जहां स्कूल की इमारत है वहां भी जान हथेली पर रखकर पढ़ाई, और जहां नहीं है वहां पेड़ के नीचे लगती है क्लास-इसके लिए जिम्मेदार कौन? -आम आदमी पार्टी



बीड: आम आदमी पार्टी की ओर से यह सवाल उठाया गया है कि देश में शिक्षा का स्तर सबसे निचले दर्जे पर पहुँच गया है, और जिला परिषद की स्कूलों की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। सरकार की कोशिश है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई ही बंद कर दी जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। राजस्थान में हाल ही में स्कूल की छत गिरने से छात्रों की मौत हुई, और नागपुर में दीवार गिरने से बच्चों की जान गई। इसी तरह बीड जिले में भी

कोई बड़ी दुर्घटना न हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया के आदेश पर पूरे देश में सरकारी स्कूलों की दयनीय हालत जनता के सामने लाने का अभियान शुरू किया है। इस सिलसिले में बीड जिले की हालत बेहद चिंताजनक पाई गई। बीड शहर से मात्र १० किलोमीटर दूर बरवटी गांव के कोठुळे वस्ती की जिला परिषद स्कूल पिछले २६ वर्षों से पेड़ के नीचे ही चल रही है। आज तक वहां कोई

कमरा नहीं बना। एक छोटा-सा शेड ज़रूर दिया गया है, लेकिन शिक्षक उसी पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह बीड शहर से करीब १२-१३ किलोमीटर दूर पिंपळवाडी रोड के पास भाळवणी गांव की वायकर वस्ती की स्कूल की छत ही नहीं है। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे और कुछ इमारत की दीवार के किनारे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। न पानी की व्यवस्था है, न टॉयलेट की। स्कूल के बगल में जानवर बंधे हुए हैं, छतों पर घास उग आई है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है।

बीड से महज ५ किलोमीटर दूर अंथरवण पिंपरी तांडा (तालुका व जिला बीड) की जिला परिषद स्कूल की छत तीन साल पहले गिर चुकी है। उस टूटी हुई छत के नीचे नए मार्बल की चमचमाती फर्श ज़रूर बना दी गई है, लेकिन छत की मरम्मत आज तक नहीं हुई। प्रधानमंत्री का नाम लिखी हुई स्वर्ण महोत्सव की नई पट्टिका भी उस टूटी इमारत पर लगाई गई है। शिक्षक उसी जंजर इमारत में पढ़ा रहे हैं और गास काटने वाले मजदूरों के बच्चे वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी हादसा कभी भी

हो सकता है - इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सब हकीकत जनता और देश के मालिक (जनता) के सामने लाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। इस अभियान में पूर्व सैनिक अशोक येडे (जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी), माउली शिंदे (जिला समिति सदस्य), कैलासचंद पालीवाल (जिला कोषाध्यक्ष), सैयद सादिक (शहर अध्यक्ष), रफीक पठान (अल्पसंख्यक विभाग प्रमुख) समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। यह जनजागरण अभियान लगातार चलता रहेगा।

गुजरात ६२% के साथ रोज़गार क्षमता में ८ वें स्थान पर

अहमदाबाद. हबीब शेख। देश के सर्वोच्च कौशल-आधारित रोज़गार क्षमता वाले शीर्ष ५ राज्यों में गुजरात शामिल नहीं है। रोज़गार क्षमता के मामले में, गुजरात ६२% के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि रोज़गार क्षमता वाले शहरों में अहमदाबाद ६०.६३% के साथ १०वें स्थान पर है। यह बात इंडिया स्किल रिपोर्ट-२०२५ में सामने आई है। एक तरह से कौशल विकास के नाम पर किए गए बड़े-बड़े दावों का सरकारी बुलबुला फूट गया है, ऐसी तस्वीर सामने आई है। देश भर के छात्रों के बीच ज्ञान, कौशल-योग्यता, व्यवहारिक घटक, कौशल अंतराल जैसे मापदंडों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ११ विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास, रोज़गार क्षमता के मुद्दे पर इंडिया स्किल रिपोर्ट २०२५ में नंबर-१ घोषित किया गया है। हालांकि, स्किल इंडिया-२०२५ में जारी रिपोर्ट में युवाओं के लिए रोज़गार क्षमता के मामले में गुजरात देश के शीर्ष-५ राज्यों में शामिल नहीं है। रिपोर्ट में छात्रों की रुचि, नियोजता की ज़रूरतें, संचार कौशल आदि जैसी बातों को शामिल किया गया है। राज्य के युवाओं को रोज़गार में कम वेतन मिल रहा है। शीर्ष-५ राज्य - अधिक रोज़गार क्षमता वाले शहर महाराष्ट्र ८४.००% पुणे (महाराष्ट्र) ७८.३२% दिल्ली ७८.००% गलुरु (कर्नाटक) ७६.४८% कर्नाटक ७५.००% मुंबई (महाराष्ट्र) ७२.४५% आंध्र प्रदेश

७२.००% नई दिल्ली ७०.२२% केरल ७१.००% तिरुसूर ७२.१५% ६२% क्षमता के साथ गुजरात ८वें स्थान पर है। रोज़गार क्षमता वाले शहरों में, अहमदाबाद ६०.६३% के साथ १०वें स्थान पर है। इस बीच, कांग्रेस ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि बड़े उद्योगों को मदद देने की भाजपा सरकार की नीति के कारण राज्य द्वारा चिन्हित छोटे उद्योगों पर ताले लग रहे हैं। जीआईडीसी के ५० प्रतिशत उद्योग अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षा संस्थान, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विश्वविद्यालय जैसी योजनाओं के बावजूद गुजरात कौशल विकास रोजगार मेलों में शीर्ष पांच राज्यों में स्थान नहीं बना सका। वर्ष २०२५ में ६०.६३% युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसमें और वृद्धि होनी चाहिए। पिछले १० वर्षों में कौशल विकास पर भारी खर्च किया गया है। लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं। बैंकिंग, वित्त, सेवा, बीमा, बीओपी, केपीकेपीओ, बीईएस, ओईएस, आईटी, डेटा सेवा, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, ऑटोमोबाइल, एमएफजी, लाजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स क्षेत्र, विमानन जैसे क्षेत्र भी सेवाओं में पिछड़े रहे हैं। गुजरात सरकार को ध्यान केन्द्रित कर कौशल विकास के नाम पर शिक्षा विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग में बदलाव लाने की ज़रूरत है।

बीड में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व अभियान शिविर उत्साहपूर्वक संपन्न

बीड, ४ अगस्त (प्रतिनिधि) - बीड शहर के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन में बीड तहसील कार्यालय की ओर से आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व अभियान शिविर उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक संदीप क्षीरसागर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उनके हाथों लाभार्थियों को राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाणपत्रों का वितरण किया गया।

बीड तहसील कार्यालय द्वारा राजस्व सप्ताह के उपलक्ष्य में सोमवार, ४ अगस्त को शहर के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन में इस शिविर का आयोजन किया गया था। इस

आ. संदीप क्षीरसागर के हाथों राजस्व विभाग के विभिन्न प्रमाणपत्रों का वितरण



अवसर पर विधायक संदीप क्षीरसागर की विशेष उपस्थिति रही।

इस शिविर में आम नागरिकों, किसानों, विद्यार्थियों और महिलाओं को निवास प्रमाणपत्र,

आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाल निवृत्ति वेतन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ३०० लाभार्थियों को मंजूरी पत्र और प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक सैयद सलीम, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, तहसीलदार चंद्रकांत शेळके, नायब तहसीलदार प्रशांत जाधव, नायब तहसीलदार अण्णासाहेब वंजारे, आपूर्ति निरीक्षण अधिकारी प्रशांत सुपेकर सहित बीड तहसील कार्यालय के कर्मचारी, बीड तालुका के विभिन्न राजस्व योजनाओं के लाभार्थी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

देसी पिस्तौल के साथ आरोपी गिरफ्तार, पिंपळनेर पुलिस की कार्रवाई

बीड, ४ अगस्त (प्रतिनिधि) - जिले के पिंपळनेर पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से देसी पिस्तौल जब्त करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम किशोर रामभाऊ माटे (उम्र ३७ वर्ष, निवासी - लोणी, तहसील व जिला बीड) है। पिंपळनेर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक मधुसूदन घुगे को कल एक गुप्त मुखबिर से जानकारी मिली कि पिंपळनेर से लोणी फाटा मार्ग पर ओंकार होटल के सामने एक व्यक्ति देसी पिस्तौल लेकर घूम रहा है। प्राम सूचना के अनुसार, सहायक पुलिस निरीक्षक घुगे ने तुरंत पुलिस उपनिरीक्षक गोलवाल, ग्रेस उपनिरीक्षक शेलके, पुलिस नाईक बांगर, पुलिस सिपाही पठान, श्री. पिंपळे और पुलिस सिपाही श्री. सानप के साथ दो पंचों को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हुए। ओंकार होटल के सामने एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर के पीछे की ओर एक आधा जंग लगा हुआ लोहे का देसी पिस्तौल मिला। पुलिस ने जब उससे पिस्तौल के लाइसेंस के बारे में पूछा तो आरोपी के पास कोई भी वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। जब किए गए देसी पिस्तौल की अनुमानित कीमत लगभग ४० हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने दो पंचों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर पिस्तौल को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत कांवत, अपर पुलिस अधीक्षक सचिन पांडकर तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी बालकृष्ण हानपुडे पाटील के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक मधुसूदन घुगे, पुलिस उपनिरीक्षक गोलवाल, ग्रेस उपनिरीक्षक शेलके, पुलिस नाईक बांगर, पुलिस सिपाही पठान, श्री. पिंपळे और पुलिस सिपाही श्री. सानप द्वारा की गई है।

पिंपरखेड जामा मस्जिद प्रकरण में दोषियों पर तुरंत मामला दर्ज किया जाए,

अन्यथा लोकतांत्रिक तरीके से तीव्र आंदोलन किया जाएगा : सैयद सलीम बाबू

बीड / प्रतिनिधि मौजे पिंपरखेड, तालुका वडवणी की जामा मस्जिद प्रकरण में दोषियों पर तत्काल आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए - ऐसी मांग तारीक-ए-इनाम संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सैयद सलीम बाबू ने की है। उन्होंने बताया कि मौजे पिंपरखेड, तालुका वडवणी में स्थित जामा मस्जिद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के अंतर्गत महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्रमांक ४५, पृष्ठ संख्या ५४-५५ के अनुसार पंजीकृत धार्मिक संपत्ति है। यह मस्जिद गांव की एकमात्र मस्जिद है। लेकिन इसी गांव के शेख महमूद शेख गफूर, शेख जाफर शेख गफूर, शेख

पाशा शेख गफूर और शेखलील शेख गफूर - इन चार भाइयों ने कुछ वर्ष पूर्व इस मस्जिद को तोड़कर उसकी लकड़ी, मिट्टी और जमीन बेचने का कार्य किया था। इस प्रकरण में मस्जिद खिदमत बहाल की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल, औरंगाबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिनांक २१/०९/२०१५ को पत्र क्रमांक ३७४/२०१५, जिला वक्फ कार्यालय बीड द्वारा पत्र क्रमांक डखड/५२७/२०२० दिनांक १३/१०/२०२०, तथा पत्र क्रमांक वक्फ/डखड विभाग-२५६/४१/२०२४ दिनांक २३/०२/२०२४ के अनुसार पुलिस निरीक्षक वडवणी थाने को इन असामाजिक तत्वों

पर कानूनी कार्रवाई करने की निर्देश दिए गए थे। फिर भी अब तक इन व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये आरोपी अब भी मस्जिद की वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, शेख महमूद शेख गफूर, शेख जाफर शेख गफूर, शेख पाशा शेख गफूर और शेखलील शेख गफूर - इन चारों भाइयों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर तीव्र कार्रवाई की जाए, अन्यथा तारीक-ए-इनाम संगठन की ओर से जिले में लोकतांत्रिक तरीके से तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा संस्थापक अध्यक्ष सैयद सलीम बाबू ने मीडिया को जारी पत्र में कहा है।

पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के कविता का आमरण अनशन शुरू

समाज की आधी आबादी आज भी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित

हैदराबाद (सोहेब आहमद कि रिपोर्ट) कामारोडू डिक्लरेशन को तुरंत पूरी तरह लागू करने की जोरदार मांग आरक्षण के बिना स्थानीय निकायों के चुनाव अस्वीकार्य मुसलमानों को अलग से १०% आरक्षण के लिए सरकार स्पष्ट बिल पेश करे मांगें पूरी न होने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की चेतावनी जन आंदोलन को एकजुट रूप से आगे ले जाने की ज़रूरत गांधीवादी सिद्धांतों के जरिए उद्देश्य प्राप्त करने का संकल्प तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष और बीआरए की एमएलसी के. कविता ने पिछड़े वर्गों (बीसी) को ४२% आरक्षण देने की मांग को लेकर ७२ घंटे के आमरण अनशन की शुरुआत की। इस मौके पर कविता ने कहा कि हमने तेलंगाना सभी वर्गों की भलाई के लिए बनाया ताकि हर

तबके को अधिकार और सम्मान मिले, लेकिन आज भी समाज की आधी आबादी यानी पिछड़े वर्ग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। तेलंगाना जागृति ने बीसी आरक्षण के लिए वर्षों से आंदोलन किया है - रैलियों, गांव-गांव जागरूकता मुहिम, राउंड टेबल सम्मेलन और जन आंदोलनों के जरिए बीसी समुदाय को संगठित किया गया और विधानसभा में बीसी आरक्षण बिल लाया गया। सरकार से लगातार कामारोडू डिक्लरेशन को पूरी तरह लागू करने और पिछड़े वर्गों को उनका पूरा हक देने की मांग की गई। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति ने हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं और यह लड़ाई किसी राजनीतिक उद्देश्य की नहीं बल्कि सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों



की है। तेलंगाना में स्थानीय निकायों के चुनाव तभी कराए जाएं जब पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि जब तक वहां बीसी को पूरा आरक्षण नहीं मिला, वहां ९ साल तक चुनाव नहीं कराए गए। कविता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को १०% अलग से आरक्षण देने के लिए सरकार को स्पष्ट बिल लाना चाहिए। बीसी

और मुस्लिम आरक्षण को अलग-अलग रखा जाए ताकि दोनों को न्याय मिल सके। कांग्रेस ने कामारोडू डिक्लरेशन में जो वादे किए हैं, उन्हें ईमानदारी से लागू करे और बीजेपी पर आरोप लगाकर बचने की कोशिश न करे। अगर केंद्र सरकार या राज्यपाल आरक्षण पर रोक लगाते हैं तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि

राज्य सरकार ने भूख हड़ताल के लिए अनुमति देने में हिचक क्यों दिखाई? अगर मुझे पुलिस स्टेशन, अस्पताल या घर में भी रखा गया, तो भी मैं वहीं से भूख हड़ताल जारी रखूंगी, क्योंकि यह पिछड़े वर्गों के भविष्य की लड़ाई है। कविता ने कहा कि पिछड़े वर्गों को संगठित होना होगा और किसी भी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप से प्रभावित हुए बिना इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। अगर राज्य सरकार वास्तव में पिछड़े वर्गों की हितैषी है तो तुरंत ४२% आरक्षण के कार्यान्वयन की घोषणा करे। जब तक पिछड़े वर्गों को उनका हक नहीं मिलता, तब तक मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। यह आंदोलन पूरी तरह गांधीजी के अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है और हम उसी रास्ते पर चलकर अपना मकसद हासिल करेंगे।

कविता के अनशन को जबरदस्त जनसमर्थन अर्जुन सिंह चौटाला ने की भागीदारी, पूर्ण समर्थन का ऐलान पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की मांग पर के. कविता के आमरण अनशन को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल (खछडक) के नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री देवी लाल के पोते अर्जुन सिंह चौटाला ने अनशन में भाग लेकर पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। इस मौके पर चौटाला ने कहा कि कविता किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि एक नेक और जायज मांग के लिए लड़ रही हैं। पिछड़े वर्गों को ४२% आरक्षण उनका हक है। हम कविता की इस लड़ाई में पूरी तरह साथ हैं, चाहे यह लड़ाई दिल्ली में हो या हैदराबाद में।